मैसर्ज एसीसी लिमिटेड, गागल सीमेंट वर्क्स, गाँव एवं डाकघर बरमाणा, जिला बिलासपुर, द्वारा गागल चूना पत्थर खदान (क्षेत्रफल 231.25 हेक्टेयर) के उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन टीपीए (चूना पत्थर, शेल और क्वार्टजाइट) और सब खनिज स्टैकिंग 2,50,000 Cum/annum (0.51 एमटीपीए) (अधिकतम) एवं1000 टीपीएच और 400 टीपीएच क्षमता वाले 02 मौजूदा क्रशर गांव बालग, नलग, बथेरह उपराली, बरमाणा, जमथल, धावन कोठी, बलोह और पंजगाईं, तहसील-सदर, जिला-बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरणीय मंजूरी के पुनर्वेधिकरण के प्रस्ताव पर दिनांक 24.08.2023 को आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यवाही ।

सामान्य कारण के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 अगस्त 2017 के फैसले के अनुसरण में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने अधिसूचना एस.ओ. 1530 (ई) दिनांक 6 अप्रैल 2018 को जारी की है और भारत में उन सभी खनन पट्टों को निर्देश दिए है जो ईआईए 1994 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त करके संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब तक ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत ईसी नहीं लिया है और उन्हें ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत मौजूदा ईसी के सत्यापन के लिए आवेदन करना होगा। और अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर परियोजना समर्थकों द्वारा आवेदन दाखिल किए जाने थे।

तदनुसार, गागल लाइमस्टोन माइंस, एसीसी लिमिटेड ने ईआईए 2006 अधिसूचना के अनुसार गागल लाइमस्टोन माइंस पर्यावरण मंजूरी के पुनर्वैधीकरण और चूना पत्थर खनन के साथ शेल और क्वार्टजाइट को शामिल करने के लिए पर्यावरण मंजूरी नियमितीकरण के लिए आवेदन दायर किया था। MoEF&CC की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और परियोजना प्रस्तावक के साथ आयोजित विभिन्न बैठकों से गुजरने के बाद, अंततः सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की शर्त के साथ शेल और क्वार्टजाइट को शामिल करने के लिए परियोजना प्रस्तावक को 27 जून 2022 को टीओआर संशोधन की अनुमति दी गई।

परियोजना प्रस्तावक ने 30 जून 2023 को क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर के कार्यालय में हिंदी और अंग्रेजी में कार्यकारी सारांश के साथ ड्राफ्ट ईआईए प्रस्तुत किया और दिनांक 24 अगस्त 2023 को उपायुक्त, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के लिए तय किया गया। संबंधित विभाग/व्यक्ति को वितरित की गई प्रतियाँ परिशिष्ट "ए" के रूप में संलग्न है।

प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु सार्वजनिक सूचना दिनांक 23.07.2023 को अंग्रेजी में और 24.07.2023 को हिंदी में दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी उसकी प्रति अनुलग्नक "बी" के रूप में संलग्न है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजगाईं, तहसील सदर, जिला। बिलासपुर (हि.प्र.) के साथ लगते मैदान में 24 अगस्त 2023 को प्रातः 11:00 बजे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों एवं समय-समय पर संशोधनों तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में जनता के विचार जानने के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई बुलाई गई थी ।

जन सुनवाई के दौरान निम्नलिखित सरकारी अधिकारी और जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	डॉ. निधि पटेल (आई.ए.एस.)	अतिरिक्त उपायुक्त	जिला। प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार
2.	श्री अतुल परमार	क्षेत्रीय अधिकारी	हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर
3.	श्री अर्पण ठाकुर	जूनियर पर्यावरण अभियंता	हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

			बिलासपुर
4.	सुश्री शैलजा चौधरी	खनन अधिकारी	खान विभाग, बिलासपुर
5.	श्री बलराज शर्मा	विस्तार अधिकारी	उद्योग विभाग, बिलासपुर
6.	श्री प्यारे लाल	जूनियर इंजीनियर	जल शक्ति विभाग, बिलासपुर
7.	सुश्री सीता धीमान	अध्यक्ष	BDC
8.	श्रीमती पूजा धीमान	प्रधान	बरमाणा पंचायत
9.	श्री सुनील धीमान	प्रधान	पंजगाई पंचायत
10.	श्री रवि गौतम	उप-प्रधान	पंजगाई पंचायत
11.	श्री रविन्द्र कुमार	प्रधान	धौन कोठी पंचायत
12.	श्रीमती कल्पना	प्रधान	जमथल पंचायत
13.	श्री बी एन शर्मा	उप-प्रधान	धौन कोठी पंचायत
14.	श्री अवधेश भारद्वाज	उप-प्रधान	बरमाणा पंचायत

सार्वजनिक सुनवाई अतिरिक्त उपायुक्त, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) की अध्यक्षता में आयोजित की गई और क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर द्वारा समन्वयित की गई। अधिकारियों और ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ उपस्थिति पत्रक अनुलग्नक "सी" के रूप में संलग्न है।

क्षेत्रीय अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त, बिलासपुर से अनुमति लेने के बाद कार्यवाही शुरू की। उन्होंने परियोजना के बारे में बताया कि यह सार्वजनिक सुनवाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों और समय-समय पर इसके संशोधनों के अनुसार, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEF&CC की अधिसूचना 1533 दिनांक 14.09.2006 द्वारा जारी टीओआर की शर्तों को पूरा करने के लिए आयोजित की जा रही है । इसके अलावा क्षेत्रीय अधिकारी ने उल्लेख किया कि प्रस्ताव 2006 में जारी अधिसूचना के तहत ईसी के पुनर्वैधीकरण के लिए है क्योंकि पहले ईसी 21.04.2005 को प्राप्त की गई थी। यह प्रस्ताव खनिज चूना पत्थर, शेल और क्वार्टजाइट के खनन के लिए है, जिनका खनन राज्य सरकार की अनुमति के अनुसार और सभी सरकारी रॉयल्टी का भुगतान करके अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जा रहा था। चूंकि ईसी पत्र दिनांक 21.04.2005 में शेल और क्वार्टजाइट का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए सार्वजनिक सुनवाई को छूट नहीं दी जा सकती और इसलिए आज आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक टिप्पणियों के समापन के बाद, क्षेत्रीय अधिकारी ने प्रस्ताव को विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए एसीसी लिमिटेड द्वारा नियुक्त पर्यावरण सलाहकार, मेसर्स जेएम एनवायरो के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया। पर्यावरण सलाहकार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना संबंधी जानकारी विस्तार से बताई। सलाहकार ने 231.25 हेक्टेयर एमएल क्षेत्र, 4.5 मिलियन टीपीए चूना पत्थर, शेल और क्वार्टजाइट की उत्पादन क्षमता, उप-ग्रेड खनिज स्टैकिंग 250000 CuM प्रति वर्ष (0.51 मिलियन टीपीए) अधिकतम) 1000 टीपीएच और 400 टीपीएच क्षमता के दो मौजूदा क्रशर गांव नालग, भटेड़ उपरली, बरमाणा, जमथल, धौन कोठी, बलोह और पंजगाईं, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश वाली गागल चूना पत्थर खदानों की पर्यावरणीय मंजूरी के पुनर्वैधीकरण के प्रस्ताव के बारे में बताया ।

कार्यक्रम के दौरान ली गई कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें एक पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी के रूप में संलग्न की जा रही हैं ।

यद्यपि जनता/जनप्रतिनिधियों ने अध्यक्ष के समक्ष अपने विचार व्यक्त किये, तथापि कार्यक्रम स्थल पर स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर के सहायता डेस्क पर जन सुनवाई के दौरान कई व्यक्तियों ने लिखित रूप में भी अपने विचार प्रस्तुत किये। इसे अनुबंध "डी" के रूप में संलग्न किया गया है ।

प्रेजेंटेशन के बाद क्षेत्रीय अधिकारी ने वहां उपस्थित जनता से इस परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर लिखित/मौखिक रूप से टिप्पणियाँ/प्रश्न/सुझाव आमंत्रित किये। हितधारकों से प्राप्त मौखिक टिप्पणियाँ/प्रश्न/सुझाव निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	मुद्दे	परियोजना प्रस्तावक की टिप्पणियाँ
1.	**श्री रमेश ठाकुर, आदर्श वेलफेयर सोसायटी गांव धौन कोठी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर ने कहा** कि राशन कार्ड में जिन परिवारों के नाम का उल्लेख है उनके बच्चों को रोजगार दिया जाना चाहिए क्योंकि बच्चे बेरोजगार हैं और उनके पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा पहले ही भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। एसीसी को स्थानीय ग्रेजुएट इंजीनियर्स /एमबीए/ आईटीआई / डिप्लोमा धारकों आदि को नियोजित करना चाहिए और कंपनी को अपने प्रशिक्षण संस्थान में स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और बाद में उन्हें कंपनी में नियोजित किया जाना चाहिए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों/विस्थापितों को जिला खनन खनिज निधि का सदस्य होना चाहिए ताकि वे अपनी पंचायतों के लिए निधियां स्वीकृत कर सकें। खनन के कारण ग्रामीणों के आसपास की भूमि में पत्थर और पानी घुस रहा है जिससे भूमि बर्बाद हो रही है। प्रशासन को इसके खिलाफ उचित कदम उठाने चाहिए। ग्रामीणों द्वारा उपयोग की जाने वाली सड़कें नष्ट हो जाती हैं और इसकी शिकायत पहले भी अधिकारियों से की गई है। इन सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए क्योंकि इन सड़कों का उपयोग लोगों द्वारा जालपा मंदिर के लिए किया जाता है। पंचायतों में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है जैसे कि कोई जंज घर, पार्किंग और अस्पताल नहीं हैं। सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी चिकित्सा सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं और प्रदान की जानी चाहिए। लगभग 20,000 आबादी आसपास के गांवों में रह रही है। एसीसी द्वारा धौन कोठी गांव की ओर बाउंड्री पिलर नहीं लगाए गए हैं। CSR की राशी विकास कार्यों के लिए धौंन कोठी पंचायत में खर्च नहीं की जाती है। जल और ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे तो हैं ही और साथ ही ब्लास्टिंग के कारण घरों में दरारें भी आ गई हैं। खदानों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इन सभी मुद्दों की रोकथाम के लिए हमारे पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता है। खनिज	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर ने क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से श्री रमेश चंद द्वारा उठाए गए टिप्पणियों/प्रश्नों पर अपने विचार देने का अनुरोध किया। **क्षेत्रीय अधिकारी का जवाब:-** क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि एक उद्योग स्थापित करने से वातावरण में प्रदूषण फेलता है और उसके प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि सीमेंट कारखाना चलाया जाता है तो धूल और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता ही है। यदि हम सतत विकास पर ध्यान देते है तो हमें गतिविधि के फायदे और नुकसान पर गौर करना होगा। विकास और निर्माण गतिविधि के लिए सीमेंट प्रमुख कच्चा माल है। इस प्रकार का उद्योग देश के विकास के लिए भी आवश्यक है। सीमेंट उद्योग में स्टोन क्रशर की स्थापना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानदंड का पालन किया जाता है और उनके द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी के अनुसार एसीसी खान क्रशर के लिए इसका पालन किया गया है। वायु प्रदूषण के संबंध में, लगभग दो साल पहले, एसीसी माइंस स्टोन क्रशर पर डंपर से चूना पत्थर उतारने के दौरान धूल को दबाने के लिए वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग कर रहा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के बाद, कंपनी ने डंपर उतारने के दौरान भगोड़े धूल को नियंत्रित करने के लिए नवीनतम तकनीक, सेंसर आधारित स्वचालित मिस्ट फॉगिंग सिस्टम प्रदान किया है, जिसका अर्थ है कि जब डंपर चूना पत्थर उतारने के लिए क्रशर हॉपर पर आता है तो डंपर की बॉडी को महसूस करने के बाद, चूना पत्थर की अनलोडिंग के

	अधिकारी बिलासपुर स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे क्षेत्र का दौरा करें। एसीसी द्वारा रात के समय प्रदूषण छोड़ा जाता है और नाइट शिफ्ट के खनन के दौरान ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न होता है। फिर भी हम खनन पुन: वैधीकरण के पक्ष में हैं क्योंकि हमने इस संयंत्र और खानों को एक पौधे की तरह पाला-पोसा है।	दौरान उत्पन्न धूल उत्सर्जन को दबाने के लिए स्वचालित रूप से मिस्ट फॉग सिस्टम संचालित हो जाता है और प्रभावी होता है। सभी पर्यावरण संबंधी डेटा के लिए विश्व के सर्वोत्तम उपकरणों द्वारा वास्तविक समय की निगरानी कंपनी द्वारा की जा रही है और 2016 से ये MoEF&CC और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के साथ-साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ये उपकरण कंपनी द्वारा स्थापित बैग हाउस के सभी चिमनियों पर स्थापित किए गए हैं। इस डेटा को हम दुनिया में कहीं भी देख सकते हैं। सीमेंट संयंत्र के संचालन के कारण वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, लेकिन इसे कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को अपनाया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कंपनी के साथ मिलकर काम नहीं करता है, क्योंकि जब भी व्यक्ति से कोई शिकायत प्राप्त होती है, उत्सर्जन को उनके घरों या इलाके में मापा जाता है। ऑनलाइन निगरानी प्रणालियों की स्थापना के बावजूद, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयंत्र का दौरा करता है और मासिक रूप से परिवेशी हवा के नमूने लेता है और साथ ही चिमनियों से हवा के नमूने भी लेता है। एसीसी लिमिटेड ने स्त्रोत पर उत्सर्जन को नियंत्रित/कम करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए हैं और यात्राओं के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम द्वारा इसकी जांच और सत्यापन किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण की स्थिति जानने के लिए नियमित रूप से मासिक निगरानी की जा रही है और यह निर्धारित मानदंडों के भीतर पाया गया है। खनन और संयंत्र संचालन के कारण शोर उत्सर्जन अधिक नहीं है। क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि उनकी टीम प्रदूषण मानदंडों पर नजर रखने और देर रात में भी फोन कॉल का जवाब देने के लिए बहुत सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मुद्दे पर कार्यवाही करने के लिए तुरंत ही अपनी टीम को नियुक्त करता है। जहां तक ब्लास्टिंग का संबंध है, संबंधित अधिकारी यहां उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह उनकी निगरानी में नहीं आता है। खनन अधिकारी ने सूचित किया है कि जहां तक

		खनन संबंधी सभी कार्यकलापों का संबंध आईबीएम द्वारा विनियमित किया जा रहा है क्योंकि यह प्रमुख खनिज के अंतर्गत आता है। IBM त्रैमासिक दौरे करता है। अध्यक्ष, अतिरिक्त उपायुक्त, बिलासपुर ने खनन अधिकारी, खनन विभाग से ओवरलोडिंग के बारे में बताने का अनुरोध किया । उन्होंने कहा कि एसीसी इसे बेहतर ढंग से समझा सकता है। फिर अध्यक्ष, अतिरिक्त उपायुक्त, बिलासपुर ने एसीसी के प्रबंधन से जनता द्वारा उठाए गए टिप्पणियों/सवालों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। एसीसी पर्यावरण प्रमुख ने बताया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार क्रेशर हॉपर पर स्वचालित मिस्ट फॉग सिस्टम स्थापित और चालू किए गए हैं। यह धुंध कोहरा प्रणाली संबद्ध बेल्ट और इसके हस्तांतरण बिंदुओं पर भी चल रही है। क्रेशर पर बैग फिल्टर लगाए गए हैं और स्थायी हॉल रोड के साथ फिक्स्ड रेन गन चालू हैं। धूल को दबाने के लिए सक्रिय खनन क्षेत्र में पानी का टैंकर तैनात किया जाता है। खानों की परिधि में न केवल एसीसी लिमिटेड द्वारा बल्कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी नियमित शोर निगरानी की जा रही है और उत्सर्जन निर्धारित सीमा के भीतर हैं। अनुपालन को सत्यापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम द्वारा धूल और शोर उत्सर्जन को भी मासिक रूप से मापा जाता है। इसके अलावा, खनन प्रमुख (एसीसी लिमिटेड) ने बताया कि ब्लास्टिंग को डीजीएमएस द्वारा विनियमित किया जाता है क्योंकि कंपन और शोर सीमा उनके द्वारा निर्धारित की जाती है। कंपनी द्वारा किए जाने वाले ब्लास्टिंग के लिए थर्ड पार्टी सर्वे किया जाता है और उसके अनुसार सीमाएं तय की जाती हैं। प्रत्येक ब्लास्टिंग का स्तर दर्ज किया जाता है और कंपन के रिकॉर्ड किए गए स्तर मासिक के साथ डीजीएमएस को प्रस्तुत किए जाते हैं। हम कोई अवैध खनन नहीं कर रहे हैं क्योंकि खनन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही किया जाता है। खनन को ऑनलाइन भी

		सत्यापित किया जाता है क्योंकि हम वार्षिक ड्रोन छवियों और वीडियो के साथ भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के पोर्टल पर डेटा जमा करते हैं। यह रियल टाइम ऑनलाइन डेटा है और इसमें हेर फेर की कोई संभावना नहीं है। ओवरलोडिंग के संबंध में एसीसी माइनिंग हेड ने बताया कि सभी सामग्री डंपर का आवागमन खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर और निर्धारित सीमा के भीतर ही है और इसके कारण सार्वजनिक या किसी अन्य परिवहन व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक पानी का सवाल है, इस साल लगातार भारी बारिश के कारण पानी की मात्रा ज्यादा थी । बलोह और कुनानू गांवों की ओर हमारे परिसर के भीतर गाद के साथ पानी को रोकने के लिए बड़ी खाइयों का निर्माण किया गया है और हमारा कार्य क्षेत्र भी इन गांवों से बहुत दूर है।
2.	**श्रीमती भावना शर्मा ग्राम पंजगाई** ने कहा कि ग्राम पंचायत पंजगाई में कई विकासात्मक गतिविधियां की गई और उन्हें आवंटित किया गया, हालांकि उनके पास ज्यादा भूमि उपलब्ध नहीं है। पंचायत भवन से महिला मंडल भवन तक एक समय में एक नाला था अब इसे एक पार्किंग के रूप में विकसित किया गया है और इसका उपयोग सामुदायिक कार्यों के लिए भी किया जाता है जैसा कि आज के समारोह में किया गया है जो एसीसी द्वारा ही निर्मित है। सामुदायिक केंद्र भी एसीसी द्वारा बनाया गया है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि रोजगार हमारे युवाओं को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने खनन ईसी और संयंत्र संचालन के पुन: सत्यापन का समर्थन किया और उन्होंने लिखित में भी समर्थन प्रस्तुत किया ।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया।
3.	**श्रीमती सुनीता देवी, बरमाणा पंचायत** ने कहा कि यह जनता आज माइंस ईसी के पुन: वैधीकरण के लिए एकत्रित हुई है, जिसके लिए हम मौखिक रूप से और लिखित रूप में भी अपनी सहमति देते हैं। वह आगे दोहराती हैं कि आज जो कुछ भी उपलब्ध है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, स्थानीय लोगों को दिया गया रोजगार केवल एसीसी के कारण है। अतिरिक्त उपायुक्त ने पूछा कि क्या उनके पास पर्यावरण प्रदूषण का कोई मुद्दा है, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया और बताया कि अगर यह संयंत्र इस क्षेत्र में संचालन में नहीं होता तो स्थानीय समुदाय को रोजगार नहीं मिल सकता था। उन्होंने खनन ईसी पुन: सत्यापन के लिए समर्थन किया और खानों के संचालन की निरंतरता के लिए अतिरिक्त उपायुक्त से अनुरोध किया।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया।

4.	**सुश्री मोनिका ग्राम पंचायत बरमाणा** ने कहा कि वह खनन ईसी के पुनः सत्यापन का समर्थन करती हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि एसीसी लिमिटेड द्वारा कई विकास कार्य किए गए। इस खदान और कारखाने के संचालन को इसी तरह जारी रखा जाना चाहिए और स्थानीय समुदाय को रोजगार वरीयता दी जानी चाहिए।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया।
5.	**श्री लच्छी राम ग्राम बिरयाही (जमथल पंचायत)** ने बताया कि वे ग्राम बिरयाही में निवासरत 25 परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि यह हमारे गांव बिरयाही और कुनानू के साथ भेदभाव क्यों है क्योंकि परियोजना रिपोर्ट में इन दोनों गाँव के नाम का उल्लेख नहीं किया गया जबकि क्रशर हमारे गांव बिरयाही से सटा हुआ है। चूंकि क्रशर गांव से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है, इसलिए हम धूल और ध्वनि प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने पूछा कि ध्वनि प्रदूषण के कारण वे कैसे प्रभावित होते हैं, तो जवाब में उन्होंने कहा कि जैसा कि आप क्रशर की क्षमता के बारे में जानते हैं और शोर उत्पन्न होता है, कंपनी ने ध्वनि अवशोषण के लिए उपाय किए थे और आगे और अधिक की आवश्यकता है। पत्थर कुचलने के दौरान धूल को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गाद से भरा पानी लगातार पास के नाले में बह रहा है और यह नाला हमारी भूमि के ऊपर लगभग 450 मीटर बह रहा है और हमारी भूमि और आस-पास की सरकारी भूमि को पार करने के बाद अंततः सतलुज नदी में विलीन हो जाता है। जैसा कि आप वर्तमान में लगातार मानसून की बारिश से अवगत हैं, यह बारिश के पानी के साथ नाले में गाद से भरे पानी की मात्रा को और बढ़ाता है। नाले की शुरुआत में कंपनी ने पहले ही 10 फीट की ऊंचाई की 200 मीटर की दीवार प्रदान की थी और आगे 250 मीटर की दीवार का निर्माण किया जाना बाकी है जो गाद को नियंत्रित करने में मदद करेगा, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। अतिरिक्त उपायुक्त आगे हस्तक्षेप करती उनके बिंदुवार संचार के तरीके की सराहना करती है और दूसरों को उसी का पालन करने की सलाह देती है। उन्होंने अध्यक्ष को यह भी बताया कि कंपनी ने पीने योग्य पानी प्रदान किया है जिसके कारण वे कंपनी के आभारी हैं। कंपनी ने गांव के बच्चों को स्कूल वैन भी प्रदान की है जिसके लिए बिरयाही गांव कंपनी का शुक्रगुजार है। उन्होंने अपने गांव में सीएसआर फंड खर्च करने का अनुरोध किया जिसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया है कि इन मुदों पर जन सुनवाई के बाद चर्चा की जाएगी क्योंकि यह जन सुनवाई के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा अतिरिक्त उपायुक्त ने क्षेत्रीय अधिकारी को कार्यवाही	क्षेत्रीय अधिकारी और परियोजना प्रस्तावक की टिप्पणियां बिंदु # 1 और # 5 के लिए बिंदु # 1 पर उत्तर दिया गया है।

	में आगे बढ़ने से पहले वक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने की सलाह दी। लोक प्रतिनिधि से संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के बाद श्री लच्छी राम ने खनन ईसी को पुनर्वेधिकर्ण करने का समर्थन किया।	
6.	**राजेश वर्मा गांव बलोह, पंचायत धौन कोठी** ने कहा कि ब्लास्टिंग के कारण उनके घरों में कंपन और दरारें पैदा हो जाती हैं और दो बार कंपनी ने उनकी भूमि का अधिग्रहण किया है। छेद में कम चार्ज का विस्फोटक डाला जाता है और अधिकारीयों की साइट यात्रा के दौरान कम कंपन ब्लास्टिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि उनके गांव बलोह की ओर कोई चेक डैम और वृक्षारोपण नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव के पास चेक डैम और वृक्षारोपण किया जाए ताकि आसपास के क्षेत्र का वातावरण स्वच्छ रहे। उन्होंने आगे कहा कि वे चाहते हैं कि संयंत्र के संचालन को जारी रखा जाए और स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि खतरे के क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी मांग की कि एसीसी को ग्रामीणों को उनके अस्पताल में चिकित्सा सुविधा प्रदान करनी चाहिए।	हेड माइनिंग (एसीसी) ने जवाब दिया कि कुछ साल पहले इस मामले पर एक शिकायत आई थी और इस पर डीजीएमएस टीम ने ब्लास्टिंग ऑपरेशन का निरीक्षण करने और कंपन की माप के लिए अपने उपकरणों के साथ साइट का दौरा किया। खदान की परिधि के आसपास कई स्थानों पर कंपन रीडिंग को मापा गया और बाद में शिकायतकर्ता के घर में चार से पांच मशीनें स्थापित की गईं। शिकायतकर्ता के घर पर कंपन दर्ज नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता की उपस्थिति में होल चार्जिंग, ब्लास्टिंग और वाइब्रेशन माप किया गया। आज की तारीख में भी हम शिकायतकर्ता की शिकायतों को सुनते हैं और उन पर ध्यान देते हैं। आगे हम तीसरे पक्ष के माध्यम से श्री राजेश के घर में कंपन को मापेंगे। इसके अलावा, खनन प्रमुख ने अध्यक्ष को सूचित किया कि खतरे का क्षेत्र परिभाषित किया गया है। पर्यावरण प्रमुख ने अध्यक्ष को सूचित किया कि परिसर के भीतर वर्षा जल प्रवाह को निर्देशित करने और रोकने के लिए सक्रिय खनन क्षेत्र के भीतर उचित नालियां बनाई गई हैं। खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास चेक डैम श्रृंखला का निर्माण किया जाता है और वे चालू हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने क्षेत्रीय अधिकारी से इसकी पुष्टि करवाई, जिस पर क्षेत्रीय अधिकारी ने अध्यक्ष को सूचित किया कि दी गई ईसी और उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक को छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट तैयार करती है और इसकी प्रति एमओईएफ और सीसी के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है । हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम ने इसे क्रॉस चेक किया। इसके अलावा क्षेत्रीय अधिकारी दोहराते हैं कि एमओईएफ और सीसी आवश्यकता के अनुसार चेक डैम उपलब्ध हैं हालांकि आगे यदि अधिक की आवश्यकता होती है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परियोजना प्रस्तावक को साइट पर इसे प्रदान करने का निर्देश देगा।

7.	**श्रीमती निर्मला देवी ग्राम बिरयाही, जमथल पंचायत** ने बताया कि फैक्ट्री एवं खदानों का संचालन निरंतर जारी रखा जाए, क्योंकि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है और हमें पेयजल, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई स्कूल बस जैसी कई सुविधाएं मिली हैं और कंपनी द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। जल प्रदूषण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण नालों में पानी का प्रवाह अधिक था, जो ज्यादा पानी को संभालने के लिए बनाए गए हैं।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
8.	**श्री कश्मीर सिंह गांव बिरयाही, जमथल पंचायत** ने कहा कि संयंत्र और खदानें चालू रहनी चाहिए। कंपनी ने बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। कंपनी समुदाय द्वारा उठाए गए आवधिक मुद्दों में भाग लेती है / हल करती है। कंपनी ने छात्रों के साथ-साथ ग्रामीणों को भी बस सुविधा प्रदान की है। कंपनी द्वारा पैदल पथ का भी निर्माण किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कंपनी द्वारा पर्याप्त वृक्षारोपण किया जाता है और इस्क्ज़ सरंक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक अवसर के दौरान वह वृक्षारोपण के दौरान भागीदार थे। कंपनी द्वारा पानी की सुविधा भी प्रदान की गयी है। उन्होंने अनुरोध किया कि खान और संयंत्र संचालन जारी रखा जाना चाहिए और युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
9.	**श्री सतीश कुमार गांव लघट, पंचायत बरमाणा** ने कहा कि वे खनन प्रस्ताव को फिर से वैध करने का समर्थन करते हैं। ढाबा मालिक, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन जैसे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का समग्र आर्थिक उत्थान केवल कंपनी के संचालन के कारण ही है। अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त ने उपरोक्त बयान के अलावा पर्यावरण पर कोई सुझाव मांगा तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई सुझाव नहीं है।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
10.	**श्री सनी शर्मा ग्राम कुनानू पंचायत पंजगाई** ने कहा कि लोडिंग और अनलोडिंग कार्यों के दौरान धूल भी उत्पन्न होती है और धूल से पशु चारा भी खराब हो जाता है। इस मुद्दे पर कोई नियंत्रण नहीं है। स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास ट्रक या नौकरी जैसी आय का कोई स्रोत नहीं है। रात के समय खानों में चूना पत्थर की लोडिंग के दौरान ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
11.	**श्री सुरेश कुमार महाजन गांव और पंचायत पंजगाई** ने कहा कि आज की बैठक पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है। प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 1984 में जब यह परियोजना शुरू की गई थी, तब से लोगों को रोजगार मिला और भविष्य में भी मिलना चाहिए। जो प्रदूषण पहले था	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।

	उसे रोक दिया गया है और वर्तमान खान संचालन के दौरान उत्पन्न नहीं होता है। ब्लास्टिंग के कारण होने वाला प्रदूषण इन दिनों उत्पन्न नहीं हो रहा है और हम एसीसी प्रबंधन के शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा उन्होंने अध्यक्ष से खानों से लगी अपनी भूमि का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया हालांकि प्रदूषण नियंत्रण में है।	
12.	**श्री शिवम गांव बरमाणा** ने बताया कि खेल के क्षेत्र में कोई गतिविधि नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि रात के समय धूल निकलती है और घरों के लैंटर पर दरारें देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमें कंपनी से कोई आपत्ति नहीं है और इसे परिचालन में रहना चाहिए, जिसके कारण विकास जारी रहेगा। हम खान ईसी पुनर्सत्यापन के लिए समर्थन करते हैं। एक अस्पताल है जहां उचित चिकित्सा जांच और समाधान प्रदान नहीं किया जाता है। अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। उन्होंने अध्यक्ष से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
13.	**अधिवक्ता नम्रता ग्राम बिरयाही पंचायत जमथल** ने कहा कि उनका घर पास में है और हमेशा डर रहता है कि उनका घर गिर जाएगा। ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया जाए जो डेंजर जोन में हो, जो आज तक नहीं की गई है।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
14.	**श्री काली दास कुनानू गांव पंजगाई पंचायत** ने कहा कि खान संचालन के कारण उन्हें रोजगार मिला है और उम्मीद है कि भविष्य में उनकी अगली पीढ़ियों को भी रोजगार मिलेगा। खदानों से सटे गांव कुनानू में हरिजन बस्ती मौजूद है, इनके मकान पास के डेंजर जोन में हैं, इन मकानों की स्थिति बहुत खराब है, इस भूमि के अधिग्रहण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कंपनी को पर्यावरण की ओर ध्यान देना जारी रखना चाहिए जबकि इस खदान और संयंत्र संचालन को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे बगीचे और पौधों की तरह है। हमारे बच्चों को रोजगार दिया जाना चाहिए।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
15.	**श्री सुरजीत ग्राम पंजगाई** ने कहा कि धूल में नैनो कणों के कारण वह और इस क्षेत्र के लोग कैंसर, अस्थमा आदि कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग के दौरान भारी कंपन उत्पन्न होता है और खनन के कारण भू-जल की क्षमता कम हो रही है। कंपनी पेड़ लगा रही है और बाद में देखभाल नहीं कर रही है।	पर्यावरण प्रमुख (एसीसी) ने बताया कि विभिन्न पोधों को लगाने के अलावा, स्थानीय वन विभाग के परामर्श से वनीकरण किया गया है। हम मौजूदा पौधों और लॉन का रखरखाव कर रहे हैं और हमारे परियोजना क्षेत्र और आसपास के समुदाय में वर्षों से नए वृक्षारोपण किए गए हैं। हमने शुरुआत से ही बंजर पहाड़ी पर एक ग्रीन पैच बनाया है और यह एक शोर अवरोधक के रूप में भी काम कर रहा है। वर्तमान वर्ष में 2000 पोधे खनन क्षेत्र में, 25 पौधे संयत्र में और 75 पौधे विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर लगाये गए।
16.	**श्री नरोतम दास गौतम, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम कुनानू पंचायत पंजगाई** ने कहा कि स्वस्थ स्वच्छ वातावरण	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

	आवश्यक है लेकिन इस खान और कारखाने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। लोग अच्छी तरह से स्थापित हैं और आर्थिक रूप से अच्छा कर सकते हैं। सामाजिक मुद्दों को दूर करने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। कारखाने को परिचालन में रहना चाहिए। लेकिन मुख्य मुद्दा बलोह-कुनानू गांव तक सड़क संपर्क का है। उन्होंने कहा कि इस गांव तक सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए क्योंकि सड़क उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। विस्फोट से उत्पन्न कंपन से घरों में दरारें पैदा होती हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए और बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहुंच मार्ग की आवश्यकता है और समस्याओं के समाधान के लिए समिति की आवश्यकता है । बलोह क्षेत्र में पौधरोपण अपर्याप्त है।	और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
17.	**श्रीमती चिंता रानी ग्राम कुनानू पंचायत धौनकोठी** ने कहा कि कंपनी ने ग्रामीणों को पौधा वितरित किया और पोस्ट केयर केवल हमारे पास है। लोग संयंत्र संचालन के कारण प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही के कारण भी प्रदूषण उत्पन्न होता है। हम कंपनी से अनुरोध करते हैं कि पर्यावरण की स्थिति में और सुधार करें और स्थानीय शिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए वरीयता भी दें।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
18.	**श्री ठाकुर दास ग्राम बरमाणा** ने बताया कि एसीसी कंपनी ने स्थानीय लोगों को कई सुविधाएं प्रदान की। कंपनी ने क्षेत्र में पर्याप्त वनीकरण किया है और स्थानीय समुदाय दाह संस्कार के लिए आवश्यक पेड़ों को काट रहा है। यदि कोई कहता है कि कंपनी द्वारा कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है तो यह गलत बयान है। उन्होंने लिखित समर्थन में भी प्रस्तुत किया। पहले हमारी बेटियां और बहनें शिक्षा के लिए जिले के भीतर बहुत दूर जाती थीं लेकिन एसीसी कंपनी ने बरमाणा में स्कूल और घुमारवीं में कॉलेज का निर्माण किया है। अत: हम खान ईसी के पुन वैधीकरण और संयंत्र प्रचालन को जारी रखने के समर्थन में हैं।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
19.	**श्री विकास चंद ग्राम बलोह पंचायत धौन कोठी** ने कहा कि पर्यावरण के संदर्भ में कंपनी ने सागवान के पेड़ लगाए थे और उस क्षेत्र में और अधिक वृक्षारोपण किया जा सकता है। भरी बारिश के पानी को रोकने के लिए चेक डैम पहले से ही वहां हैं लेकिन उस क्षेत्र में और अधिक चेक डैम बनाया जा सकते है। वृक्षारोपण देखभाल ग्रामीणों के दायरे में है और आगे क्षेत्र में और अधिक वृक्षारोपण किया जा सकता है।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
20.	**श्री नंदलाल चंदेल पंचायत बेरी रजादिया** ने कहा कि कंपनी की स्थापना के बाद क्षेत्र में कई विकासात्मक गतिविधियां की गई हैं लेकिन प्रदूषण के कारण कुछ प्रभाव भी पड़ा है। कंपनी	एसीसी पर्यावरण प्रमुख ने अध्यक्ष को सूचित किया कि वे रात के समय ब्लास्टिंग नहीं करते हैं। दूसरा स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ

	के साथ दो प्रकार के समुदाय जुड़े हुए हैं, एक जो रोजगार के माध्यम से या अन्य साधनों से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है और दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जिनकी भूमि खदानों से सटी हुई है और स्वेच्छा से अपनी भूमि कंपनी को सौंपना चाहते हैं। एसीसी कंपनी की नीति कभी भी स्थानीय आबादी के हित के खिलाफ नहीं थी, लेकिन अगर कंपनी भूमि अधिग्रहण करती है तो उन्हें 04 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। मवेशियों के चारे की घास में बहुत धूल हो जाती है । अतिरिक्त उपायुक्त हस्तक्षेप करती है और बताती है कि यह बिंदु इस सार्वजनिक सुनवाई से संबंधित नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया कि रात में ब्लास्टिंग की जाती है, और यह बेरी तक ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह संयंत्र काम करना जारी रखना चाहिए लेकिन एसीसी प्रबंधन से हमारा अनुरोध है कि हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करें। अस्पताल में दो डॉक्टर हैं जो केवल मरीजों को पट्टी प्रदान कर सकते हैं अन्यथा अस्पताल में कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। एसीसी अस्पताल में स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए । सीएसआर फंड को कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए कोचिंग के लिए स्थानीय स्कूल के छात्रों पर खर्च किया जाना चाहिए ।	वर्ष पूर्व पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के माध्यम से एक स्वास्थ्य अध्ययन किया था जिसमें यह पाया गया था कि परियोजना क्षेत्र के आसपास रहने वाले मनुष्यों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि यदि कोई बीमारियां हैं तो वे व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई व्यक्तिगत जीवन शैली के कारण हैं। यह भी बताया गया कि हमारा ओएचसी एक मान्यता प्राप्त डीओटी केंद्र और नामित माइक्रोस्कोपी केंद्र (डीएमसी) है और विभिन्न आवधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। यह भी जोड़ा गया कि हमारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) है और यह एक अस्पताल नहीं है। रोगियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाती है और आगे उन्हें विशेषज्ञ के पास अस्पताल में भेजा जाता है। । सभी कर्मचारियों की निवारक चिकित्सा जांच एसीसी ओएचसी में की जाती है और इसकी रिपोर्ट एमओईएफ एंड सीसी के साथ प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा एमओईएफ और सीसी के पास प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को उनके क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रमुख ने बताया कि हर साल सामाजिक वानिकी के तहत न केवल हमारे खनन पट्टा क्षेत्र में बल्कि आसपास की पंचायतों में वृक्षारोपण किया जाता है।
21.	**श्री सुशील शर्मा पूर्व अध्यक्ष पंचायत पंजगाई** ने कहा कि यह संयंत्र तीन दशकों से अधिक समय से चल रहा है। स्थानीय पंचायतें लाभार्थी हैं और उन्हें बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि एसीसी कंपनी द्वारा पूर्व में कई विकासात्मक गतिविधियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। इस संयंत्र और खदानों को सभी पहलुओं में संचालित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त उपायुक्त ने परियोजना प्रस्तावक से रोजगार पर जवाब मांगा। उन्होंने आगे बताया कि वह संयंत्र के संचालन के समर्थन में हैं।	एसीसी लिमिटेड के मुख्य संयंत्र प्रबंधक ने जवाब दिया और बताया कि एसीसी प्लांट में लगभग 73% हिमाचली कार्यरत हैं जिनमें से 50% जिला बिलासपुर से हैं और 30% आसपास की पंचायतों से हैं। इसके अलावा 32 प्रशिक्षु पास की पंचायतों से हैं। 18 जुलाई 2023 को स्थानीय समुदाय के सहयोग से हमने सेना, पुलिस सेवाओं, वन रक्षकों और अन्य सेवाओं के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अपने परिसर में अपनी तरह का एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। हम चारों पंचायतों के युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि एसीसी आसपास की पंचायतों के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीशियन, एयरोड्रम सहायता प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा है।
22.	**श्री बंत सिंह चंदेल गांव बेरी रजादिया** ने कहा कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे हल किया जाना चाहिए।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

	उन्होंने एसीसी प्रबंधन से अनुरोध किया कि एक और संयंत्र चालू करके ऐसे मुद्दों को हल करने पर जोर दिया जाए । शिक्षित युवा अपने घरों तक ही सीमित है और इस मुद्दे को रोजगार देकर ही हल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एसीसी कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में जो भी विकास किया जाता है, उसके बारे में कभी नहीं सुना गया है कि यह देश के अन्य क्षेत्रों में किया गया हो । उन्होंने बताया कि इन पंचायतों के लगभग 70-80 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से कंपनी से जुड़े हैं। उन्होंने आगे दोहराया कि आज एकत्र हुए 90% से अधिक लोग खान ईसी के पुन: सत्यापन के समर्थन में हैं। उन्होंने रोजगार संबंधी समस्या के बारे में चर्चा की।	और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
23.	**श्री राकेश चौधरी ग्राम एवं पंचायत जमथल** के ने कहा कि रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिए। वह खान ईसी पुनर्सत्यापन के समर्थन में भी हैं।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
24.	**श्री सीताराम शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम एवं पंचायत पंजगाई** ने कहा कि परियोजना रिपोर्ट ठीक से नहीं दिखाई गई है। एसीसी ने इस क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं लेकिन ब्लास्टिंग से बहुत कंपन होता है, जिससे घरों में दरारें आ जाती हैं। इन टूटे हुए घरों को कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाए और अधिक वनीकरण किया जाना चाहिए।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
25.	**श्री भगत सिंह वर्मा ग्राम बलोह पंचायत धौनकोठी** ने कहा कि प्रदूषण सभी उद्योगों द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि यह एक खनन परियोजना है, हालांकि प्रदूषण उत्पन्न होता है लेकिन इसका उपचार किया जाना चाहिए। डीएमएफटी निधि लगभग 80 करोड़ रुपये है और ज्ञापन के अनुसार हमारे लिए धन उपलब्ध नहीं है। खर्च के लिए बढ़ाया गया क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र उपेक्षित है। डीएमएफटी का यह पैसा प्रभावित गांवों में खर्च किया जाए और इसके आधार पर पर्यावरण संरक्षण किया जाएगा। पूर्व की भांति स्थानीय युवाओं को रोजगार वरीयता दी जानी चाहिए। उन्होंने भी खान ईसी और संयंत्र संचालन के पुन: सत्यापन की जोरदार सिफारिश की। सीएसआर व्यय को आसपास की पंचायतों में विवेकपूर्ण और प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। प्रदूषण को बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन रोजगार दिया जाना चाहिए।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
26.	**श्री रमेश कुमार गौतम ग्राम कुनानू** ने कहा कि खनन क्षेत्र में पानी की समस्या है। कंपनी को खनन क्षेत्र में उचित जल निकासी स्थापित करनी चाहिए और बलोह और अन्य क्षेत्रों में आगे वृक्षारोपण के लिए सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने संयंत्र के संचालन और खान ईसी के पुन: सत्यापन का समर्थन किया।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
27.	**श्रीमती चिंता देवी ग्राम बिरयाही** ने कहा कि उनके बच्चों को	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय

	रोजगार दिया जाना चाहिए। और क्रशर के पास उसके घर में दरार है और उसके बच्चे बेरोजगार हैं। कारखाने के बंद होने के दौरान जीवित रहना मुश्किल था। उन्होंने भी संयंत्र और खानों के संचालन को जारी रखने का समर्थन किया।	अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
28.	**श्री सुनील गौतम गांव कुनानू** ने बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए और हम खान ईसी पुनर्सत्यापन का समर्थन करते हैं।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
29.	**श्री अमित गौतम गांव और पंचायत पंजगाई** ने कहा कि वह खनन ईसी के पुन: सत्यापन का समर्थन करते हैं। एसीसी द्वारा बहुत विकास किया गया है और स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
30.	**श्री विक्रांत डोगरा ग्राम बरमाणा (खटेर)** ने कहा कि मेरा घर एक नाले के पास है जहां एसटीपी का शोधित पानी छोड़ा जा रहा है और अभी तक इस नाले की सफाई नहीं हुई है।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
31.	श्री हरीश ठाकुर ग्राम भटेर, पंचायत बरमाणा ने सीमेंट उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। एसीसी डीएवी स्कूल बरमाणा में स्थानीय बच्चों के लिए स्कूल फीस में कोई छूट नहीं है। एसीसी कंपनी ने स्थानीय क्षेत्रों में कोई सोलर लाइट नहीं लगाई है। उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए एसीसी कंपनी में नौकरियां प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।
32.	**श्री शिव सिंह वर्मा ग्राम बलोह, पंचायत धौनकोठी** ने कहा कि कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करने वाले हजारों लोगों की सहायता करती है। अधिक रोजगार की आवश्यकता है। प्लास्टिक कचरे को स्थानीय क्षेत्र जैसे बलोह, धौन कोठी आदि से भी एकत्र किया जाना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि वह संयंत्र संचालन के समर्थन में हैं।	पर्यावरण प्रमुख ने कहा कि एसीसी ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2009 से स्वेच्छा से प्लास्टिक कचरे का संग्रह शुरू कर दिया है, जिस दिन हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा अध्यक्ष को यह भी बताया गया कि आसपास के गांवों से लगभग 2600 टन प्लास्टिक एकत्र किया गया है और 1000 टन पाइन नीडल्स को एकत्र किया गया है और भट्ठे में सह-संसाधित किया गया है।
33.	**श्री रवि कुमार शर्मा उप-प्रधान ग्राम पंजगाई** ने सभी 4 पंचायतों (पंजगाई , धौनकोठी, बरमाणा और जमथल) की ओर से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन स्थानीय लोगों को रोजगार दे और स्थानीय युवाओं को शत-प्रतिशत अवसर दिया जाए। इन लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने खान ईसी और निरंतर संयंत्र संचालन के पुन: सत्यापन का भी जोरदार समर्थन किया। पंचायत को डीएमएफटी फंड दिया जाए ।	अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोट किया गया ।

	स्थानीय निवासियों को रियायती मूल्य पर सीमेंट दिया जाए । सीएसआर फंड को बढ़ाएं और इसे स्थानीय पंचायतों के विकास में खर्च करें। ब्लास्टिंग के कारण जिन मकानों में दरारें आ रही हैं, उन्हें डीएमएफटी फंड से मुआवजा दिया जाए। क्षेत्र में आईटीआई जैसे कुछ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान खोले जाए । किसी भी तरह का अधिग्रहण होने की स्थिति में भूमि के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। जालपा मंदिर के लिए डीएमएफटी फंड से सड़कों का निर्माण किया जाए । भविष्य में ढुलाई हेतु परिवहन कार्य केवल उपर्युक्त 4 पंचायतों के लोगों को दिया जाए । बरमाणा पंचायत में पीने के पानी के लिए कुछ मुद्दे आए हैं जिन्हें तुरंत हल किया जाना चाहिए। श्मशान स्थल (श्मशान घाट) स्थल को सीएसआर मद से ठीक से स्थापित किया जाना चाहिए। 2013 में एसीसी कंपनी स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लिए लिखित में सुनिश्चित करती है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सीएसआर के माध्यम से किए गए एसीसी के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने इन पंचायतों में हाल के दिनों में किए गए सभी प्रमुख कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने उपरोक्त प्रस्ताव को अन्य पंचायत प्रधानों के साथ अध्यक्ष को लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया।	

इसके अलावा, खान ईसी के पुन: सत्यापन के समर्थन में सभा द्वारा लगभग छह सौ से अधिक समर्थन पत्र प्रस्तुत किए गए और अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से 02 अभ्यावेदन प्राप्त हुए । जन सुनवाई के दौरान महिलाओं और युवाओं सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

अतिरिक्त उपायुक्त
बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
Additional Deputy Commissioner
Bilaspur District, H.P